सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 9 ● अंक: 185 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 10 अगस्त, 2023
मूल्य ₹ 3/-

यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा।

-अब्दुल कलाम

शुभमन गिल और कुलदीप ने लगाई... 7 | यूपी में जातिगत जनगणना बन सकता... 3 | क्या अब जनहित के मुद्दे न उठाने... 2

सदन में मोदी पर बरसे खरगे, बोले

भगवान नहीं हैं प्रधानमंत्री

- अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा दिन
- लोकसभा में बहस जारी, राज्यसभा में हंगामा
- सीतारमण ने विपक्ष पर किया हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के तीसरे दिन भी आज सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी बहस जा रही है। विपक्षी दलों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव (नियम 267) के तहत चर्चा आरंभ कराने की अपनी जिद से पीछे हटते हुए नियम 167 के अंतर्गत चर्चा शुरु कराने का प्रस्ताव दिया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी सदन में मौजूद हों। हालांकि सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं दिखा। वहीं हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

उधर लोकसभा में वित्त मंत्री ने कांग्रेस में जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि यूपीए ने देश को पीछे धकेल दिया। उधर पर विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि गोयल से विपक्षी नेताओं की मुलाकात हुई थी उसके बाद चर्चा की गई। बता दें कि चर्चा के अंत में आज शाम पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। 26 जुलाई को विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया था और बहस के लिए 8 से 10 अगस्त का समय तय किया था। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने सरकार और पीएम मोदी से तीन सवाल पूछे,उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी आज लोकसभा में इन सवालों के जवाब देंगे।

बुधवार को राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए वहां के लोगों की आपबीती सुनाई और सरकार पर तीखे हमले बोले थे। अब तक की बहस में विपक्ष की तरफ से मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई है। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई, राहुल गांधी, ललन सिंह जैसे नेता अपना पक्ष रख चुके हैं जबकि सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे, किरेन रिजेजू, स्मृति ईरानी और खुद गृह मंत्री अमित शाह पक्ष रख चुके हैं. आज विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर पक्ष रखेंगे।

पीएम परमात्मा नहीं, उनके आने से क्या होने वाला है : खरगे

संसद के मानसून सत्र के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है वो? वे कोई भगवान नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''वे (सत्ता पक्ष) चाहते थे कि नियम 176 के तहत चर्चा हो जबकि हम नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। बीच का रास्ता निकालने के लिए हमने नियम 167 के तहत चर्चा कराने का प्रस्ताव दिया।'' खरगे ने कहा, ''अब इसमें दिक्तत क्या है। नियम 167 के तहत चर्चा होने दें। प्रधानमंत्री को आने दो। हम अपना विषय रखेंगे।'' इसी समय सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा और शोरगुल आरंभ कर दिया। हंगामा होता देख, खरगे ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा, '' वह परमात्मा हैं क्या...? कोई भगवान तो नहीं हैं...।''

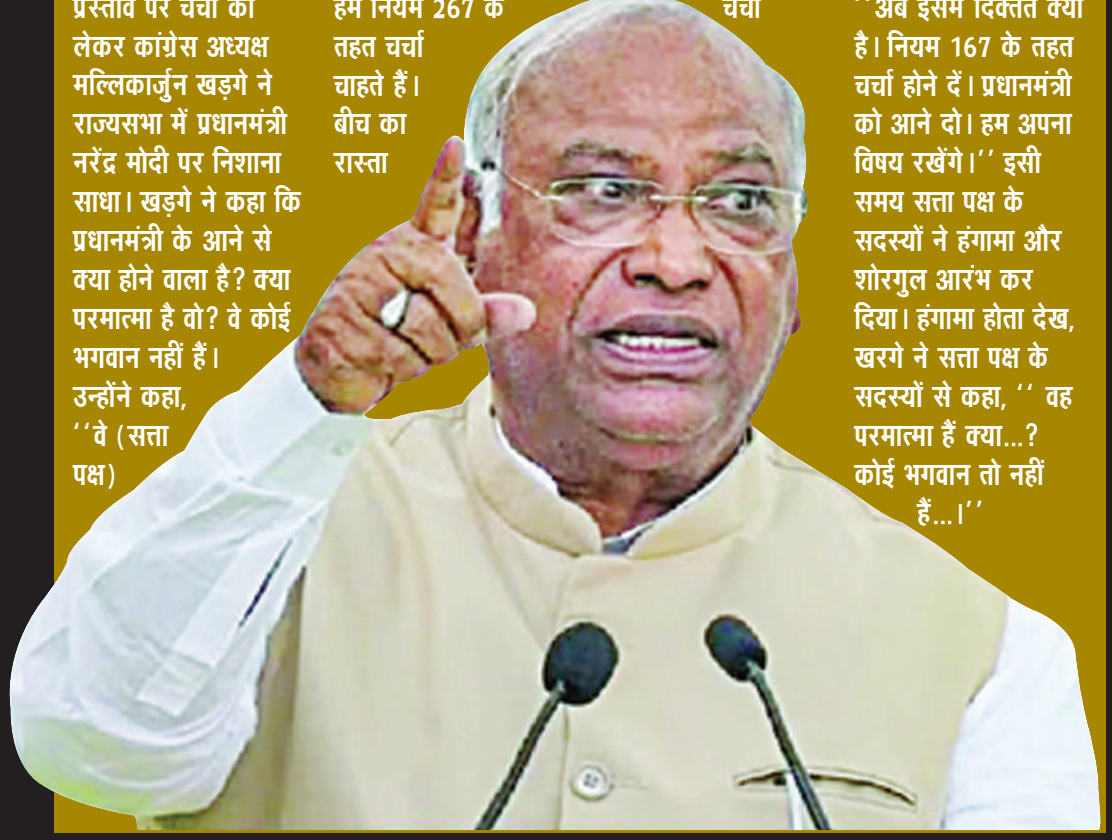

आज जवाब देंगे पीएम मोदी

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज (10 अगस्त) लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पीएमओ ने गुरुवार को ट्वीट किया, पीएम आज शाम 4:00 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (9 अगस्त) को निचले सदन को सूचित किया, अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए पीएम कल सदन में मौजूद रहेंगे। सदन स्थगित होने से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ने इसकी पुष्टि की।

आप सपने दिखाते हैं, हम सपने साकार करते हैं : सीतारमण

लोकसभा में तीसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया मंदी का सामना कर रही है, वहीं भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आम लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं लाई। 6 दशकों से गरीब हटाओ, सुनते रहे, लेकिन क्या सचमुच गरीबी हटी क्या? यूपीए सरकार में गरीबी नहीं हटी, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में गरीब हटी। पीएम की नीतियों की वजह से हम आगे बढ़े। आम लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। आप सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बनेगा, मिलेगा जैसे शब्द अब प्रचलन में नहीं हैं। आजकल लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गया, मिल गया, आ गया. यूपीए के कार्यकाल के दौरान लोग कहते थे बिजली आएगी, अब लोग कहते हैं बिजली आ गई। उन्होंने कहा गैस कनेक्शन मिलेगा, अब गैस कनेक्शन मिल गया...उन्होंने कहा एयरपोर्ट बनेगा, अब एयरपोर्ट बन गया।

पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर भी कुछ बोलतीं स्मृति : मोइत्रा

फ्लाइंग किस विवाद पर गुरुवार (10 अगस्त) को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर हमारी पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली और अब फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं। बुधवार को स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया कि संसद से जाते समय उन्होंने फ्लाइंग किस का इशारा किया, जबकि उस समय महिला सांसद भी बैठी थीं। इसके बाद कई महिला बीजेपी सांसदों ने राहुल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नया विवाद शुरू हो गया है जहां बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावार है तो वहीं कई विपक्षी सांसद राहुल के समर्थन में आ गए हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा, कि जब बीजेपी सांसद पर हमारी चैंपियन रेस्लर्स के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तब केंद्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री ने कुछ नहीं कहा।अब वह फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं।

क्या अब जनहित के मुद्दे न उठाने का नियम आएगा : अखिलेश

» नियमावली पर कसा तंज- टमाटर खाकर विस में आना मना होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा की नई नियमावली पर पर जमकर बरसे है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि लगता है यूपी विधानसभा में प्रतिबंध के लिए अब और कुछ नियम आएंगे। उन्होंने कहा कि टमाटर खाकर आना मना, सांड पर बात नहीं करना, जनहित व सौहार्द के मुद्दे उठाना मना, स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं, बेरोजगारी व महंगाई शब्द का प्रयोग मना, जातीय जनगणना और पीडीए पर सांकेतिक भाषा में भी बात करना मना जैसे नियम आएंगे।

वहीं सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व मेंपार्टी के सभी विधायकों और पदाधिकारियों ने अगस्त क्रांति के महानायकों के अधूरे सपनों को पूरा करने और पीडीए (इंडिया) के 11 संकल्पों को पूरा करने की शपथ ली। इसमें समाजवाद लाने, भाजपा को हटाकर विश्व में भारत के लोकतंत्र को ऊपर ले जाने और इसका मान बढ़ाने के संकल्प प्रमुख रहे। इस अवसर पर अखिलेश ने कहा कि महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों व समाजवादियों ने जो सपने देखे थे, वे अधूरे रह गए हैं। हम 11-सूत्रीय संकल्पों के साथ देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। कार्यक्रम में कवि और वरिष्ठ सपा नेता उदय प्रताप सिंह ने 11-सूत्रीय संकल्प पत्र पड़ा, जिसे सभी ने दुहराया। ये संकल्प थे-खुशहाल यूपी खुशहाल इंडिया बनाकर रहेंगे। समाज में धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को बढ़ाएंगे। संविधान बचाएंगे, सामाजिक न्याय, सस्ती और समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। गरीबी हटाने, रोजगार लाने और अमीरी-गरीबी का फासला कम करने के लिए आजीवन संघर्ष करेंगे। पर्यावरण संरक्षण करेंगे और ध्वनि प्रदूषण कम करेंगे। श्रमिक व किसान को अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाएंगे। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकार दिलाएंगे। धरती बचाने के हिमालय, वृक्ष और नदियां बचाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के जरिये संघ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा नहीं लगाया था,, वो उसी की भरपाई में आज यह नारे लगा रहे हैं। भाजपा के राज में जो लोग पहले से भगाए गए हैं, वो पहले से जाकर किसी और के आने के लिए तंबू तैयार करने वाले लोग हैं। यह है भाजपा का अपने लोगों को भारत छुड़वाया आंदोलन।

अंबेडकर के संविधान को कमजोर कर रही है भाजपा

अखिलेश ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया था, उस संविधान को आज सत्ता में बैठे लोग कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लेने के बजाय उसके बहिष्कार का काम किया था। भाजपा राज में रोजगार के क्षेत्र में और लोकतांत्रिक देशों की गिनती में लोगों को सामान्य सुविधाओं के सूचकांक में हमारी स्थिति दयनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर की र्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने तंत्र पर भरोसा नहीं, बल्कि इसके लिए एक अमेरिकी कंपनी को 300 करोड़ रुपये देने जा रहे हैं। सदन के अंदर भी पूछे गए सवालों का सटीक जवाब देने के बजाय सीएम इधर-उधर की बातें बतियाने लगते हैं।

बीजेपी को हराना है तो ईमानदारी से रहें एकजुट : ममता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम पर राज्य में बीजेपी के साथ गुप्त समझौता करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि वे चुपचाप पश्चिम बंगाल में भाजपा से हाथ मिला रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। न्यूनतम राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए। प्रत्येक पार्टी को राजनीतिक विचारधारा की एक निश्चित लाइन का पालन करना चाहिए।

अगर वे इस रणनीति को जारी रखते हैं, तो मैं यह कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि टीएमसी भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ है। ममता ने इंडिया के संबंध में कांग्रेस-सीपीएम पर दोहरे मानदंडों का रास्ता अपनाने का भी आरोप लगाया। ममता ने कहा, जबकि विपरीत दल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और सीपीएम पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऑक्सीजन प्रदान कर रही हैं।

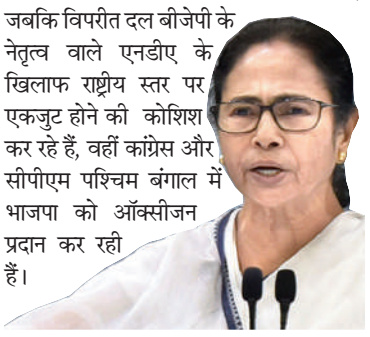

पुलिस की कार्यप्रणाली पर नजर रखें : वरुण

अफसर की दोबारा तैनाती पर उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बरेली। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बरेली की बहेड़ी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाने के बाद बातचीत में स्थानीय पुलिस अधिकारी पर निशाना साधा है। साथ ही जांच के बाद कार्रवाई पर नजर रखने की बात कही है। उन्हें बताया गया है कि एसएसपी ने एसपी देहात को जांच सौंपी है। सांसद ने कहा कि जांच में क्या होता है, अब उस पर नजर रख रहे हैं। एक अधिकारी तबादले के बाद भी यहां तैनाती पर आ गए हैं। उन्हें यह मिलीभगत जैसा लगता है। उन्हें पीड़ितों से ढंग से बात करना नहीं आता।

ऐसा मेरे संसदीय क्षेत्र में तो नहीं चलेगा। सांसद ने कहा कि जो अफसर जनता की सुनेगा, जनता के काम करेगा वही मेरी पसंद होगा। बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में जब भी कोई मीटिंग की तो हर बार पुलिस को सुधरने की हिदायत दी। स्थानीय स्तर पर तैनात अफसरों से लेकर नीचे तक सभी की कुंडली खंगाली जाए तो सच सामने आ जाएगा। भाजपा सांसद ने बहेड़ी पुलिस के खिलाफ आए दिन मिल रहीं शिकायतों को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा था। जिसमें आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से बहेड़ी क्षेत्र में नशे और जुआ का काला कारोबार फल फूल रहा है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

अनुच्छेद-370 भावनाओं से जुड़ा मामला

» सुप्रीम कोर्ट में बहस से महबूबा मुफ्ती खुश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भाग्यशाली है कि उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारे लोगों को उन्हीं तर्कों के लिए या तो गिरफ्तार या फिर घर में नजरबंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं शुभचिंतकों को बताना चाहती हूं कि मेरे लिए और जम्मू-कश्मीर के अधिकांश लोगों के लिए अनुच्छेद -370 सिर्फ एक कानूनी या सांविधानिक मामला नहीं है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ा है। संसद में लिए गए फैसले ने संविधान को रौंद दिया है।

मुफ्ती ने अनुच्छेद-370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई दलीलों पर खुशी जताई है। शीर्ष अदालत, अनुच्छेद-370 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को रद्द करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। शीर्ष अदालत में दलीलों से यह स्पष्ट हो गया है कि संसद के पास अनुच्छेद-370 को तब तक निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश नहीं करती। उन्होंने कहा कि वहां कोई विधान सभा नहीं थी, सत्यपाल मलिक को संविधान सभा बनाया गया, उनके सलाहकारों को मंत्रिपरिषद बनाया गया, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है?

सितंबर में हो सकता है निकाय चुनाव का एलान

जम्मू-कश्मीर में नगर निगमों के साथ ही स्थानीय निकाय के चुनाव का एलान सितंबर में हो सकता है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से सितंबर में ही चुनाव मानकर तैयारी की जा रही है। इस बीच नगर निकायों में कोई वार्ड नहीं बढ़ाए गए हैं। मतदान ईवीएम के जरिये होगा। जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर विभिन्न जिलों में नगर परिषद व नगरपालिका के 970 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। जम्मू नगर निगम के 75 और श्रीनगर के 74 वार्डों के साथ पूरे प्रदेश में 1119 वार्डों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। दो नगर निगमों के अलावा 75 नगर पालिका व नगर परिषद हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही संभाग जम्मू और कश्मीर में चार चरणों में चुनाव हो सकते हैं। नामांकन तथा मतदान व परिणाम की घोषणा के साथ ही पूरी चुनाव प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी कर ली जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि निकाय चुनाव की तिथियों को लेकर शिक्षा विभाग से छुट्टियों का ब्योरा मंगा लिया गया है। इसके साथ ही ईवीएम के रेंडमाइजेशन, मतदान कर्मियों की तैनाती तथा सुरक्षा इंतजाम का खाका तैयार कर लिया गया है।

भाजपा ने सिर्फ झूठ की राजनीति की : कांग्रेस

» हिमाचल सरकार के मंत्रियों ने पूर्व सीएम पर बोला हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिमला। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश की जनता को ठगा और आज भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने प्रेस बयान में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम राहत राशि जारी करने के दावे झूठे हैं, केंद्र से अंतरिम राहत की पहली किश्त तक जारी नहीं हुई है।

जयराम जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑडिट पैरा के कारण पिछले वर्षों की रुकी 315 करोड़ की राहत राशि में से केंद्र ने 189 करो? जारी किए हैं। ऑडिट की आपत्तियों को मौजूदा सरकार ने दूर किया है। जयराम सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछले पांच सालों में भाजपा ने सिर्फ डबल इंजन का ढिंढोरा पीटा लेकिन प्रदेश को कुछ नहीं मिला। केंद्र ने सिर्फ एसडीआरएफ के तहत 360 करोड़ प्रदेश को दिए हैं जो प्रदेश का हक है और सभी राज्यों को दिए जाते हैं। आपदा से प्रदेश को 8000 करोड़ का नुकसान हुआ है, केंद्र की टीम ने राज्य का दौरा भी किया है, लेकिन केंद्र से अभी एक पैसा भी जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर राज्य के हालात से अवगत करवा है और अंतरिम राहत की पहली किश्त जारी करने की मांग की है।

केंद्र से अभी तक नहीं मिली आपदा की सहायता राशि

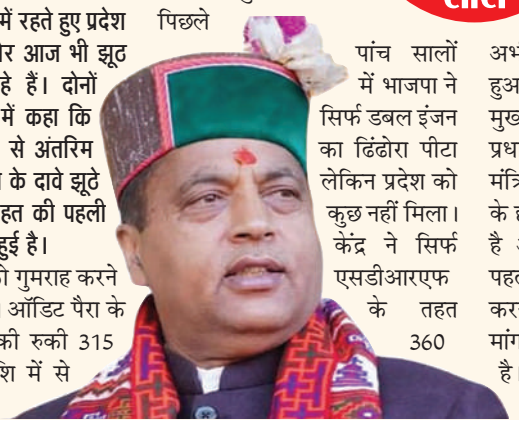

राघव के खिलाफ झूठी अफवाह फैला रही बीजेपी : संजय

नई दिल्ली। सांसदों के फर्जी सिग्नेचर मामले पर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी के दौरान संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राघव चड्ढा के खिलाफ भाजपा झूठ फैला रही है। उन्हें फंसाया जा रहा है। आप ने भाजपा पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। पीसी के दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा लागातार दुष्प्रचार कर रही है। इन्हें दर्द कि युवा नेता ने सवाल कैसे पूछा। कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है। फर्जी दस्तखत की अफवाह फैलाई जा रही है। भाजपा नेता वो कागज दिखाएं, जिसमें फर्जी साइन हुए हैं। फर्जी दस्तखत की अफवाह फैलाई जा रही है। हस्ताक्षर की बात पूरी तरह से गलत है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है।

यूपी में जातिगत जनगणना बन सकता है सियासी मुद्दा

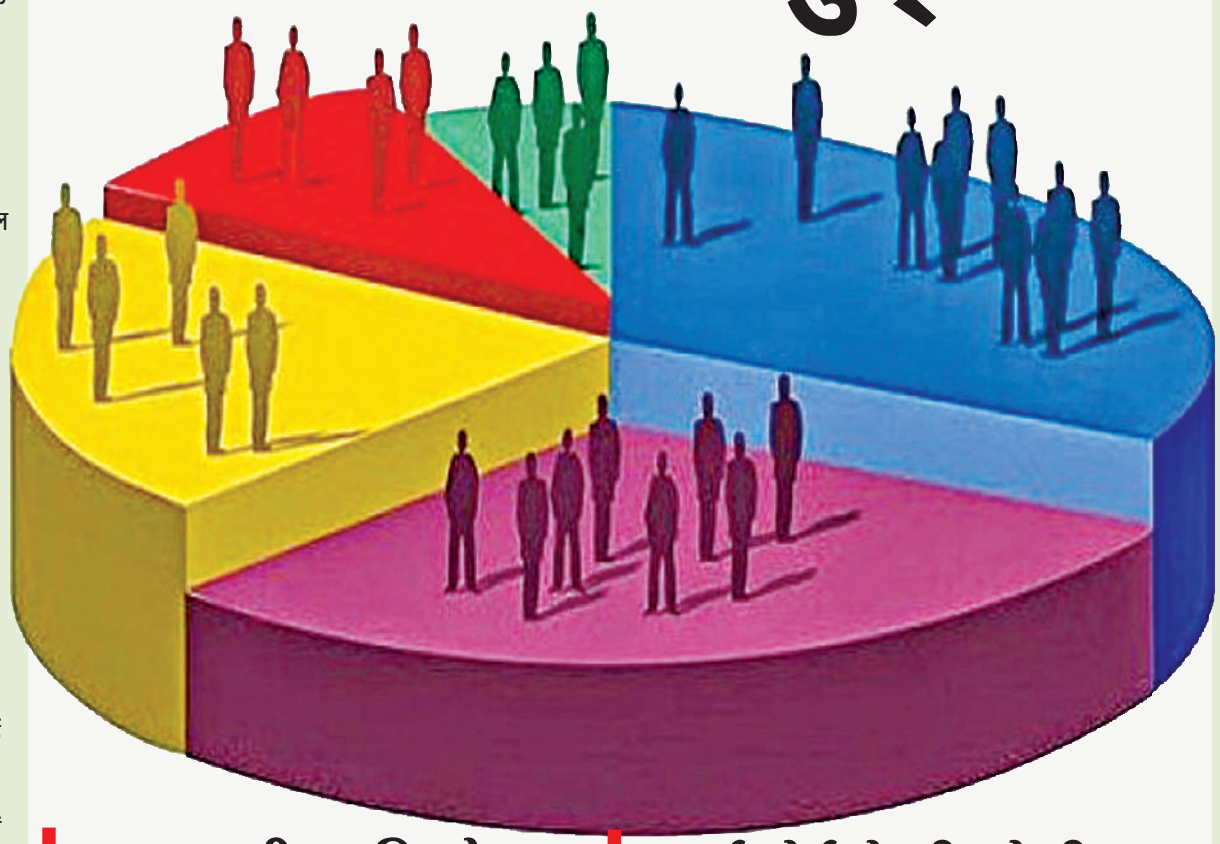

आजाद भारत में पहली बार 1951 में हुई थी जनगणना

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेज़ों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर भारत सरकार ने नीतिगत फ़ैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज़ किया है। लेकिन 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों ने तथाकथित ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ-साथ तथाकथित निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया। साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन इस सिफ़ारिश को 1990 में लागू किया जा सका. इसके बाद देशभर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए थे।चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय-समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आख़िरकार साल 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों की मांग के बाद सरकार इसके लिए राज़ी हुई थी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 में की गई सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। सरकार के मुताबिक़ इस जनगणना में कई तरह की विसंगतियां थीं।

बीजेपी को कोर वोट बैंक के नाराज होने का डर

बीजेपी नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। उनको पता है कि जो पिछड़े हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी। बीजेपी को लगता है कि इससे अगड़ी जाति का उसका वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। विपक्ष संख्या के आधार पर सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाता है कि सरकार नौकरियों में कटौती कर रही है, ऐसे में उसकी मांग का कितना असर होगा? पिछड़ों को बर्तन में पानी भरकर चांद दिखाया जा रहा है,इस मांग का दबाव भले ही बीजेपी पर पड़े लेकिन चुनावों में यह बहुत असरदार होगा, ऐसा नहीं लगता है, जो लोग हाशिए पर हैं उनका केवल पढ़ा-लिखा तबका ही इस तरह की मांग से खुद जोड़ता है। विपक्ष को मौक़ा मिला है इसलिए वो गोलबंद होकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जनगणना कराने से बेरोज़गारी, एनएसएसओ के आंकड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आत्महत्या, कोविड में हुए जानमाल का नुक़सान, साल 2021 की जनगणना अगर समय पर हो जाती तो इससे मिलने वाले आंकड़े साल 2011-21 के बीच के होते और इसमें ज़्यादातर कार्यकाल मोदी सरकार का ही है। जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है. इससे जो भी नकारात्मक आंकड़े सामने आएंगे उसकी ज़िम्मेवारी बीजेपी की होगी। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत बीजेपी के कई नेता समय-समय पर आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना से जो आंकड़े सामने आएंगे उसका दबाव बीजेपी के ऊपर होगा, विपक्ष इस बात को समझता है और इसलिए उसने जातिगत जनगणना की मांग की है ताकि चुनावों में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। जातिगत समीकरण को तोड़ने के लिए अब बहुत सारे विकल्प हैं जैस, ग़रीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं. यानि इस तरह से उनको अपने पक्ष में करना ज़्यादा आसान है।

मायावती, अखिलेश व खाबरी ने उठाई मांग

हाईकोर्ट ने भी योगी सरकार को किया तलब

» लोस चुनाव में बीजेपी को घेर सकता है विपक्ष

सिद्धार्थ शर्मा

लखनऊ। जातिगत जनगणना की मांग बिहार से होते हुए यूपी में भी पहुंच गयी है। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी व केंद्र सरकार से प्रदेश में भी इसे लागू करवाने की मांग की है। यही नही यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है यूपी सरकार से अदालत ने जवाब-तलब किया है। वहीं सपा, सुभासपा तक भी कई बार मांग कर चुकी है कि जातिगत जनगणना करवाई जाए।

कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर कई बार आवाज उठाई है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्षी पार्टियों के तेवर से ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर भाजपा घिरती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर हाल ही में लखनऊ में एक सम्मेलन भी आयोजित किया था। आने वाले दिनों में, पार्टी जनगणना के लाभों के बारे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सचेत करने के लिए ऐसे और अधिक कार्यक्रमों और राज्य भर में ग्रामीण स्तर पर पहुंच बनाने की योजना बना रही है। इस तरह के सम्मेलन यूपी में कांग्रेस के लिए नई बात है, जो राज्य में मुख्य रूप से उच्च जाति की पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी ने राज्य सरकार से सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को कानून द्वारा गारंटीकृत प्रतिशत के अनुसार भरने की भी मांग की थी। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है लेकिन उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि नौकरियों में ओबीसी का प्रतिशत काफी कम है। इसे भी जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।

चुनावी एजेंडा है : प्रशांत किशोर

जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी पैदल यात्रा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर होते रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं इनको समाज के बेहतरी से लेना-देना नहीं है। जातिगत जनगणना तो अंतिम दाव खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार 18 सालों से सत्ता में हैं लेकिन जातिगत जनगणना वह आज क्यों करवा रहे हैं? नीतीश कुमार को 18 सालों से जातिगत जनगणना याद नहीं आ रहा था? फिर उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। दरअसल सरकार जातिगत जनगणना नहीं बल्कि सर्वे करवा रही है। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। सर्वे और जनगणना में जमीन और आसमान का फर्क है। सर्वे का कोई लीगल एंटीटी नहीं है। सरकार ने इस बात को कभी स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी ? उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं। राज्य सरकार सर्वे कभी भी करा सकती है मान लीजिए अगर लीगल एंटीटी मिल भी गई तो जातियों के जनगणना मात्र से लोगों की स्थिति सुधरेगी नहीं। जनगणना के मुताबिक बिहार के 13 करोड़ लोग सबसे गरीब और पिछड़े हैं, यह जानकारी सरकार के पास है तो फिर इसे सुधारते क्यों नहीं। दलितों की जनगणना आजादी के बाद से हो रही है फिर उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना भी हुई है लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है? बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब है पर कोई इस पर बात नहीं कर रहा है।

1980 में कांशीराम ने की सबसे पहले मांग

जातियों की जनसंख्या के मुताबिक़ आरक्षण की मांग सबसे पहले 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता कांशीराम ने की थी। यूपी की समाजवादी पार्टी भी जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। दक्षिण भारत की कई पार्टियां इस तरह की जनगणना की मांग करती रही हैं। जबकि बिहार सरकार ने भी इसी साल जातिगत सर्वेक्षण की शुरुआत कराई थी, लेकिन यह मामला फ़िलिहाल कोर्ट में लंबित है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने का फ़ैसला पिछले साल जून में हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार में नीतीश कुमार की सहयोगी थी और उसने इस फ़ैसले का समर्थन किया था। जातिगत जनगणना की बात आते ही अक्सर बहुत सी चिंताएं और सवाल भी उठ खड़े होते हैं. इनमें से एक बड़ी चिंता ये है कि इसके आंकड़ों के आधार पर देशभर में आरक्षण की नई मांग शुरू हो जाएगी.

इंडिया गठबंधन बनाएगा मुद्दा

इसमें विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है, इसका मक़सद अलग-अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और ज़रूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया जाता है। सबसे पहले बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराए जाने का फ़ैसला किया था। वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने और दलित, पिछड़े वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010-11 में देशभर में आर्थिक-सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे।

यूपी सरकार भी करवाए जातिगत जनगणना : मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में जातिवार जनगणना को 'पूर्णत: वैध' ठहराये जाने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं कि इस राज्य में यह प्रक्रिया कब शुरू होगी। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ''ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णत: वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं कि यहां यह जरूरी प्रक्रिया कब शुरू होगी?''उन्होंने इसी सिलसिले में किये गये एक अन्य ट्वीट में कहा, ''देश के कई राज्यों में जातीय जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसे कराने की मांग लगातार ज़ोर पकड़ रही है, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है, यह अति-चिन्तनीय है। बसपा की मांग है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए।'' बसपा अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मण्डल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्त्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित एवं शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदार बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

उम्मीदों के करीब पहुंचा चंद्रयान मिशन

भारत का चंद्रयान-3 मिशन बुधवार को चांद के और करीब पहुंच गया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट ने चांद की कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। गौरतलब है कि 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा छोड़ 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया था।

धीरे-धीरे भारत का चंद्रयान-3 चांद के और करीब पहुंच गया है इसी के साथ भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत व 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें भी दुनिया के आकाश में पहुंच जाएंगी। हालांकि इस मिशन को सफलता उस दिन मिलेगी जब यह यान चांद की धरती पर उतर जाएगा। इस सफलता के साथ ही भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा जिसका यान चंद्रमा पर लैंड हुआ होगा। इस पूरे मिशन की सफलता का श्रेय इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने पूरे मनोयोग से इस मिशन को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत का चंद्रयान-3 मिशन बुधवार को चांद के और करीब पहुंच गया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट ने चांद की कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। गौरतलब है कि 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा छोड़ 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया था।

*इसरो ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रयान-3 अब चांद की सतह के और करीब है। चंद्रयान-3 के ऑर्बिट कम करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इसकी दूरी 174 किमी*1437 किमी रह गई है। इसरो ने कहा कि अब यान का चांद की कक्षा बदलने से जुड़ा ऑपरेशन 14 अगस्त को दिन में 11.30 से 12.30 के बीच होगा। जैसे-जैसे मिशन आगे बढ़ रहा है चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में और नीचे उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि इसे चांद के ध्रुव पर पहुंचाया जा सके। 15 जुलाई को चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद चंद्रयान ने 17 जुलाई को पृथ्वी की दूसरी और 18 जुलाई को पृथ्वी की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद 20 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी की चौथी और 25 जुलाई को पृथ्वी की पांचवीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक अगस्त को भारत के बहुप्रतीक्षित अभियान चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया था। पांच अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। इसके बाद चंद्रयान-3 से खींची गई कई तस्वीरों को इसरो ने साझा भी किया था। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केन्द्र से उड़ान भरी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता।*

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

घरेलू बाजार में महंगाई नियंत्रण की कवायद

नंदकिशोर सोमानी

भारत सरकार द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद वैश्विक खाद्यान्न संकट और अधिक गहरा गया है। रूस के काला सागर अनाज समझौते से बाहर निकल जाने के कारण दुनिया के बाजार पहले से ही खाद्यान्न संकट से जूझ रहे थे। अब भारत सरकार के इस फैसले ने बाजार की नींद उड़ा दी है। प्रतिबंध की खबर आते ही वैश्विक बाजारों में हलचल बढ़ गई। जनता से लेकर व्यापारियों तक ने चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सुपर मार्केट्स में चावल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। दुकानों के बाहर ग्राहकों की लंबी कतारें दिख रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो माल रास्ते में है, उसकी कीमत भी 50-100 डॉलर प्रति टन तक बढ़ गई है। पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने आक्रामक रुख दिखाया है और कहा है कि भारत को प्रतिबंध हटा लेना चाहिए अन्यथा जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए।

दरअसल, पिछले कुछ समय से देश के भीतर खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। चावल की घरेलू कीमतों में साल भर में करीब 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। विपक्ष महंगाई के नाम पर सरकार को कठघरे में खड़े कर रहा है। टमाटर की कीमतों को लेकर लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं। अगले कुछ महीनों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार को अंदेशा था कि अनाज की बढ़ती हुई कीमतें चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। इसलिए सरकार ने घरेलू बाजार में गैर-बासमती चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया। हालांकि, इससे पहले सरकार ने पिछले साल अगस्त में गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी का निर्यात शुल्क लगा कर देश में चावल की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन न देखकर अब इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालांकि, सरकार के इस निर्णय को सियासी लाभ की दृष्टि से उठाया हुआ कदम कहा जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों के लिए अकेले भारत को ही जिम्मेदार ठहरना सही नहीं है। दरअसल, दुनियाभर में निर्यात होने

वाले चावल की 90 फीसदी फसल एशिया में पैदा होती है। पिछले कुछ समय से अल-नीनो और मौसम में बदलाव की वजह से चावल उत्पादन में कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। उत्पादन से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण बड़े अनाज व्यापारियों ने चावल का स्टॉक करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। द्वितीय, रूस के काला सागर अनाज समझौते से बाहर निकलने के निर्णय के चलते खाद्यान्न की कीमतें बड़ी। अब भारत सरकार के इस फैसले के बाद उसमें और तेजी आ गई। तृतीय, चावल निर्यात करने वाले देशों की सूची में भारत के बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। चावल निर्यात के मामले में दोनों देशों को भारत का प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। जुलाई अंत में भारत ने जैसे ही चावल निर्यात पर रोक का ऐलान किया वैसे ही इन दोनों देशों ने निर्यात पर 10 फीसदी कीमतें बढ़ा दी। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल महंगा हो गया। वहीं देश के भीतर चावल की कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुए इजाफे को कहा जा रहा है। भारत पिछले कुछ वर्षों से दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक देश बना हुआ है। विश्व के कुल चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। करीब 140 देश भारत से गैर बासमती चावल खरीदते हैं। साल 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 22.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था। देश से गैर-बासमती चावल का कुल निर्यात 2022-23 में 4.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। जो इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में 3.3 मिलियन डॉलर का था।

मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-जून) में 15.54 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 35 फीसदी ज्यादा है। दरअसल, दुनिया के चार सबसे बड़े निर्यातक देश थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका चावल का जितना निर्यात करते हैं, भारत अकेला उनसे अधिक निर्यात करता है। ऐसे में भारत द्वारा चावल निर्यात पर रोक लगाए जाने के फैसले बाद वैश्विक आपूर्ति में करीब एक करोड़ टन की कमी आ सकती है। थाईलैंड और वियतनाम की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस बड़ी कमी को पूरा कर सकें।

आम आदमी के जीवन में भी दिखे विकास की खुशी

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में तीन अगस्त को आर्थिक शोध व बाजार पर नजर रखने वाले दुनिया के दो दिग्गज वैश्विक वित्तीय संगठनों— ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टेनली और एस एंड पी ग्लोबल द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लंबी तेजी का दौर शुरू हो गया है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत आर्थिक शक्ति बनने की डगर पर अग्रसर है। कोई एक वर्ष पहले दुनिया के प्रमुख आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में कहा जा रहा था कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा रखने वाला भारत वर्ष 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगा, लेकिन इन दिनों प्रकाशित हो रही रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दे सकता है।

हाल ही में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ), अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टेनली जैसे कई वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आएगा। इतना ही नहीं, 30 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल भारत में जो प्रति व्यक्ति आय 2450 डॉलर है, वह वर्ष 2030 तक 70 फीसदी बढ़कर 4000 डॉलर प्रति व्यक्ति हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 27 जुलाई को जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शोध इकाई इकोरैप की रिपोर्ट में भी कहा किया गया है कि भारत वर्ष 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 8 फीसदी से ज्यादा रहने वाली है। इससे चालू वित्त वर्ष के दौरान सालाना विकास दर के 6.5 फीसदी रहने की संभावना बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2027 तक अमेरिकी इकोनॉमी का आकार 31.09 ट्रिलियन डॉलर का होगा और यह पहले स्थान पर होगी। दूसरे स्थान पर चीन 25.72 ट्रिलियन डॉलर के साथ होगा।

तीसरे स्थान पर भारत 5.15 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में दोबारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र परिसर (आईईसीसी) 'भारत मंडपम' राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में वृद्धि की रफ्तार और तेज होगी और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इस दावे की तार्किकता है कि क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था स्थिर हो चुकी है और जर्मनी की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा संबंधी रिपोर्ट-2023, इनवेस्को ग्लोबल की 'सोवरेन वेल्थ फंड निवेश रिपोर्ट-2023', निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की 'भारत की आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023' को भारत की बढ़ती हुई आर्थिक, वित्तीय और निवेश अहमियत को रेखांकित करते हुए दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा संबंधी रिपोर्ट में भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में आगे पहुंच गया है।

इनवेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश को लेकर दुनिया के 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया है। इनवेस्को के अध्ययन के मुताबिक भारत की कारोबारी व राजनीतिक स्थिरता में बढ़ोतरी हो रही है जो उसका मजबूत पक्ष है। राजकोषीय घाटा कम हो रहा है और राजस्व संग्रह में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा भारत की आबादी, नियामक पहल और सोवरेन निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल से भी भारत को निवेश की पहली पसंद बनने में मदद मिली है। विकासशील देशों में निवेश के लिए अब चीन नहीं बल्कि भारत निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। इसी तरह निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि भारत की 1.4 अरब की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गई है, इसलिए भारत की जीडीपी में प्रभावी रूप से विस्तार होने का अनुमान है।

अनुमान लगाया कि अगले 20 वर्षों में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का निर्भरता अनुपात सबसे कम होगा। यह वास्तव में भारत के लिए विनिर्माण क्षमता स्थापित करने, सेवाओं में वृद्धि जारी रखने, बुनियादी ढांचे के विकास को जारी रखने के मामले में सही होने की खिड़की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए नवाचार और बढ़ती श्रमिक उत्पादकता महत्वपूर्ण होने जा रही है। पूंजी निवेश भी भविष्य में विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होगा। बढ़ती आय और गहरे वित्तीय क्षेत्र के विकास के साथ, अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण भारत की बचत दर बढ़ने की उम्मीद है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ाने में बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई क्रांति अहम भूमिका निभा रही है। पिछले लगभग एक दशक में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उद्योग-कारोबार को आसान बनाने के लिए 1,500 पुराने कानूनों और 40 हजार अनावश्यक अनुपालन को समाप्त किए जाने की अहम भूमिका है।

सावन के महीने में घूमें महादेव की नगरी

सावन का महीना चल रहा है। सावन में भोलेनाथ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है, ऐसे में लोग महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिरों और शिवालयों में जा रहे हैं। अगर बात करें महादेव की नगरी काशी की तो वाराणसी में महादेव के काफी सदियों पुराने मंदिर हैं, जिस वजह से लोग दूर-दूर से वहां दर्शन के लिए आते हैं। ना सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशों के भी लोग भोलेनाथ की नगरी घूमने आते हैं। दरअसल, आप आसानी से वीकेंड में वाराणसी जाने का प्लान बना सकते हैं।

तंग गलियों में पैदल जाएं

बनारस की तंग गलियां अपने आप में काफी अलग हैं। ऐसे में आप कैब या गाड़ी को छोड़ कर पैदल ही बनारस की गलियों में घूमें। यहां के लोगों से बातचीत करें।

वाराणसी में महादेव के काफी सदियों पुराने मंदिर हैं, जिस वजह से लोग दूर-दूर से वहां दर्शन के लिए आते हैं।

नाव से घूमें घाट

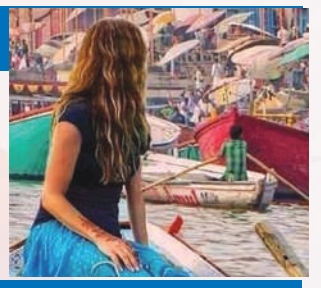

नावों से घाट घूमने जरूर निकलें। अगर आप रात के समय घाटों का शानदार नजारा देखना चाहते हैं तो नाव से बनारस के सभी घाट घूम सकते हैं।

लस्सी का उठाएं लुत्फ

मिट्टी के कुल्लड़ में मिलने वाली लस्सी का स्वाद ही कुछ और है। ऐसे में बनारस जाकर गाढ़ी लस्सी और मोटी मलाई की परत आपके मुंह के स्वाद को दोगुना कर देगी।

अंत में खाएं बनारस पान

वो गाना तो आपने सुना ही होगा, खइके पान बनारस वाला। तो बस अपनी बनारस की ट्रिप को बनारसी पान खाकर अंत कीजिए।

लें स्ट्रीट फूड का आनंद

बनारस का खाना काफी ज्यादा चर्चित है। ऐसे में आप वाराणसी की सड़कों पर मिलने वाले कचौड़ी-सब्जी और रबड़ी-जलेबी का आनंद जरूर लें।

गंगा आरती जरूर देखें

अगर आप महादेव की नगरी काशी घूमने जा रहे हैं तो गंगा आरती को अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। गंगा आरती को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आप पारंपरिक तरह से गंगा आरती देखना चाहते हैं तो अस्सी घाट पहुंच जाएं।

हंसना मना है

मैडम दूध वाले से.. छोरे पैंतीस साल का होने को आया, अब तो शादी करले! दूध वाला नहीं नहीं! मैडम क्यों? क्या हुआ? दूधवाला मै रोज सुबह पांच बजे उठ कर घरों में दूध देने जाता हूं, उस वक्त इन औरतों का ओरिजिनल चेहरा देख कर मेरी तो शादी करने कि हिम्मत ही नहीं होती?

हनीमून पर गए एक जोड़े ने बड़ी सी होटल में रूम लेने के लिए इंट्री ली। पत्नी को सोफे पर बिठा कर पति काउंटर पर रूम बुक करने गया। वहां पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में काउंटर पर खड़ी थी। रूम में आकर पति पत्नी से बोला- वो जो काउंटर पर लड़की खड़ी थी न वो कॉल गर्ल थी..। पत्नी- नहीं जी ये उनका युनिफोर्म होता है आप तो कुछ भी समझ लेते है। दोनों में बहस हो गयी और शर्त लग गयी। पति ने पत्नी को परदे के पीछे छुपा दिया और उस लड़की को रूम में बुलाया और फिर उससे पूछा-मैं अकेला हूं आज रात भर मेरे साथ रुकोगी? वह लड़की बोली-2000 रुपये लूंगी। वह बोला-200 रुपये दूंगा..और वह लड़की गुस्सा होकर चली गयी। शर्त पति जीत गया। फिर शाम को दोनों पति-पत्नी रेस्टरेंट में बैठे हुए थे। तो उस लड़की ने दूर से उन्हें देखा और पास आकर आदमी को बोली ।200 रूपये में ऐसी ही मिलेगी . .तिये।

कहानी | हाथी की रस्सी

एक बार एक आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक वयस्क हाथी दिखा, जो बहुत ही विशालकाय था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद वह एक कमजोर रस्सी से बंधा हुआ था। वह आदमी अचानक वहां रुक गया। उसे यह देख कर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना बड़ा हाथी एक कमजोर रस्सी के सहारे बंधा रह सकता है। जबकि हाथी में इतनी शक्ति होती है, कि वो बड़े से बड़े पेड़ों, पहाड़ों को हिला सकता है, वह चाहे तो जंजीरों को तोड़ सकता है, लेकिन वो इन रस्सियों से बंधा हुआ है। जब कि वहां कोई जंजीर, पिंजड़ा नहीं है। कारण को जानने के उद्देश्य से वह महावत के पास गया और उत्सुकता पूर्वक उसने अपनी जिज्ञासा रखी। उसके महावत से पूछा श्रीमान, यह विशालकाय हाथी जो एक सेकंड में तहस नहस कर सकता है, ऐसा क्या कारण है, जिसकी वजह से यह एक कमजोर सी रस्सी से बंधा हुआ है? और भागने की कोशिश भी नहीं करता? उस आदमी की बात सुनकर महावत ने उत्तर दिया, जब यह हाथी बहुत छोटा था, तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांधा करता था, उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी, कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था, उस समय इसने उस रस्सी को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, कई बार चोटिल भी हुआ, पैरों से खून भी निकला, लेकिन इसके लिए रस्सी तोड़ पाना मुमकिन नहीं हुआ। और असंभव मान कर रस्सी पर जोर लगाना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे जब यह बड़ा हुआ। इसे अभी भी लगता था, की यह रस्सी इससे नहीं टूटेगी। अत: यह इसे तोड़ने में असमर्थ है। इसने रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आज यह एक वयस्क बलवान, विशालकाय हाथी है। लेकिन इसने रस्सी से हार मान ली। हालांकि यह किसी भी समय रस्सी को तोड़कर अपने आपको बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन बचपन की हार को जीवन की हार मानकर यह अब कोशिश ही नहीं करता। फलस्वरूप यह केवल एक कमजोर रस्सी से ही बंधा रहता है। यह बात जानकर वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ।

7 अंतर खोजें

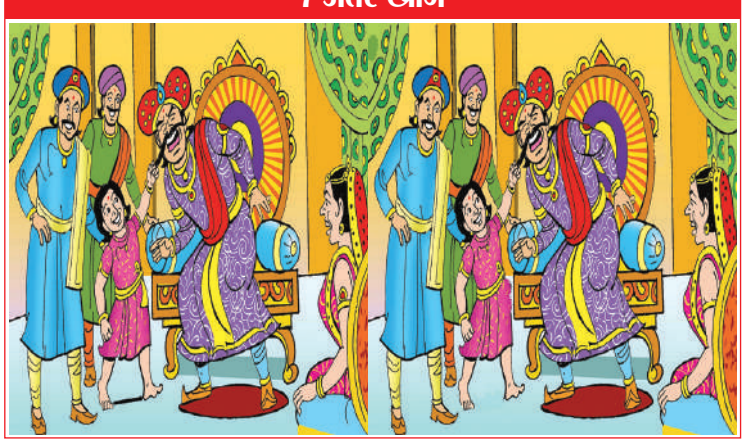

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवेक से कार्य करें। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से लाभ होगा। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं।

वृषभ पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा। मनोरंजन का समय मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा। कारोबारी वृद्धि की योजना बनेगी।

मिथुन बुरी खबर प्राप्त हो सकती है। दौड़धूप अधिक होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। काम में मन नहीं लगेगा।

कर्क थकान व कमजोरी रह सकती है। खान-पान पर ध्यान दें। घर-परिवार की चिंता बनी रहेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मान-सम्मान मिलेगा।

सिंह विवाद को बढ़ावा न दें। हल्की हंसी-मजाक करने से बचें। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। आत्मसम्मान बनेगा। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी।

कन्या उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति पर व्यय होगा। व्यापार लाभदायक रहेगा। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी।

तुला स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। विवाद को बढ़ावा न दें। बनते काम बिगड़ सकते हैं। तनाव रहेगा। व्यापार ठीक चलेगा। यात्रा में विशेष सावधानी रखें।

वृश्चिक दूर से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें। यात्रा मनोरंजक रहेगी।

धनु लेन-देन में जल्दबाजी न करें। समय अनुकूल है। कोई आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी। योजना फलीभूत होगी।

मकर वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। कानूनी अड़चन दूर होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। मनोरंजन के साधन प्राप्त होंगे।

कुम्भ मित्रों तथा रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। मनोरंजन होगा। चोट व दुर्घटना से हानि संभव है। जल्दबाजी व लापरवाही भारी पड़ सकती है।

मीन बुद्धि का प्रयोग किसी भी समस्या का निवारण कर सकता है, यह याद रखें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

बॉलीवुड | मन की बात

सिक्स पैक नहीं अपने अभिनय पर ध्यान दें युवा अभिनेता : अभिषेक

अभिनेता अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म घूमर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता और सैयामी खेर स्टारर यह बहुप्रतीक्षित फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में वह फिल्म का प्रचार करने अलग-अलग इवेंट में पहुंच रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी बातों का खुलासा कर रहे हैं। इसी क्रम में अभिषेक बच्चन ने हाल ही में कहा कि उन्हें युवा अभिनेताओं का बॉडीबिल्डिंग के प्रति जुनून बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जूनियर बच्चन का मानना है कि उन्हें सिक्स-पैक एब्स दिखाने के बजाय अपने अभिनय कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने आजकल के अभिनेताओं के सिक्स-पैक एब्स की तरफ जुनून को लेकर अपनी हैरानी जताई। अभिनेता ने कहा कि वह सिक्स-पैक एब्स के एक्टर्स के जुनून को देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा, इन दिनों युवा अभिनेताओं का मानना है कि वे सिर्फ सिक्स-पैक एब्स बनाकर अभिनेता बन सकते हैं। भाई, अपनी भाषा पर ध्यान दें.... अपने अभिनय कौशल पर काम करें। यही अभिनेता बनाता है, न कि शरीर। अभिषेक बच्चन ने इस इंटरव्यू में धूम में एक फिट पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका को भी याद किया। अभिनेता का मानना है कि अगर भूमिका की मांग हुई तो वह एब्स पर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा, जय दीक्षित एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसे फिट रहना था, लेकिन वह ऐसा नहीं था जो अपनी शर्ट उतारकर सिक्स-पैक एब्स दिखाता हो। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सनी देओल ने युवा अभिनेताओं द्वारा अपने शरीर के बाल काटने और एब्स दिखाने पर भी कटाक्ष किया था। अभिषेक बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता जल्द ही, आर बाल्की की घूमर में सैयामी खेर के साथ दिखाई देंगे। फिल्म में वह एक कोच की भूमिका निभा रहे हैं, जो सैयामी के किरदार को कोचिंग देता है और उसे देश के लिए खेलने के लिए प्रेरित करता है। यह फिल्म 18 अगस्त को सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

भावनाओं के समंदर में गोते लगाने आ रही गोल्डफिश

कल्कि और दीप्ति नवल से सजी फिल्म का ट्रेलर जारी

भावनाओं के समंदर में गोते लगाने के लिए गोल्डफिश तैयार हो चुकी है। स्प्लेंडिड फिल्म्स ने मंगलवार (8 अगस्त) को फिल्म का ट्रेलर जारी किया। ट्रेलर में अनामिका (कल्कि केकलां) और साधना (दीप्ति नवल) की दुनिया दिखाई गई, जो अपने खट्टे-मीठे रिश्ते से जूझती नजर आती हैं। फिल्म में कल्कि केकलां और दीप्ति नवल के अलावा जाने-माने अभिनेता रजित कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि गोल्डफिश एंटरटेनिंग फिल्म साबित हो सकती है।

मानसिक सेहत से जूझ रहे किसी व्यक्ति या परिवार को पॉजिटिव सपोर्ट को बढ़ावा देना ही फिल्म का मूल विषय है। स्प्लेंडिड फिल्म का ताल्लुक एमपावर से है, जो आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। डॉ. नीरजा बिड़ला के नेतृत्व में चल रहे एमपावर का मकसद मानसिक सेहत के मसलों की वकालत करना, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम से लेकर समग्र देखभाल से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

गोल्डफिश फिल्म की स्टार कास्ट

दीप्ति नवल, रजित कपूर और पुशन कृपलानी के अलावा साइकोलॉजिस्ट दिलशाद खुराना और एमपावर की हेड ने मानसिक सेहत से संबंधित चुनौतियों और इसका सामना करने के तरीकों के महत्व, प्रभाव और बारीकियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमपावर की लेट्स टॉक वन टू वन टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 120 820050 है, जो मानसिक सेहत से संबंधित दिक्कतों से जूझ रहे व्यक्ति को समाधान उपलब्ध कराने का एक ठोस प्रयास है।

25 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

पुशन कृपलानी ने बताया कि गोल्डफिश की शुरुआत मनोभ्रंश, पहचान और प्रवासी लोगों के बारे में बनने वाली फिल्म के रूप में हुई थी। हालांकि, जब इस फिल्म से कलाकार जुड़ते चले गए और विचारों का आदान-प्रदान हुआ तो नया विषय ही सामने आ गया। फिल्म की मूल कहानी की बात करें तो गोल्डफिश क्षमा और मानवता को बरकरार रखने की कहानी है। दीप्ति नवल और कल्कि केकलां ने अपने-अपने किरदारों में जान फूंक दी है।

उन्होंने बताया कि भारत में फिल्म की रिलीज को लेकर पूरी टीम उत्साहित है और यह जानने के लिए बेचैन है कि भारतीय दर्शकों से इस फिल्म को कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। बता दें कि यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को रिलीज होगी।

अल्लू अर्जुन ने किया 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' से इनकार

तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर लाइमलाइट में हैं। अपने लंबे करियर में, उन्होंने टॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है। उनमें से कुछ हैं आर्य, बनी और पुष्पा: द राइज। बीते कुछ समय से अल्लू अर्जुन अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरें थीं कि सुपरस्टार, आदित्य धर की महत्वाकांक्षी फिल्म द इम्मोर्टल अश्वत्थामा से बॉलीवुड में कदम रखेंगे। वहीं, अब इसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे फैंस को झटका लग सकता है।

हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्लू अर्जुन ने फिल्म द इम्मोर्टल अश्वत्थामा को करने से मना कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अल्लू अर्जुन शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को साइन करने को लेकर असमंजस में थे।

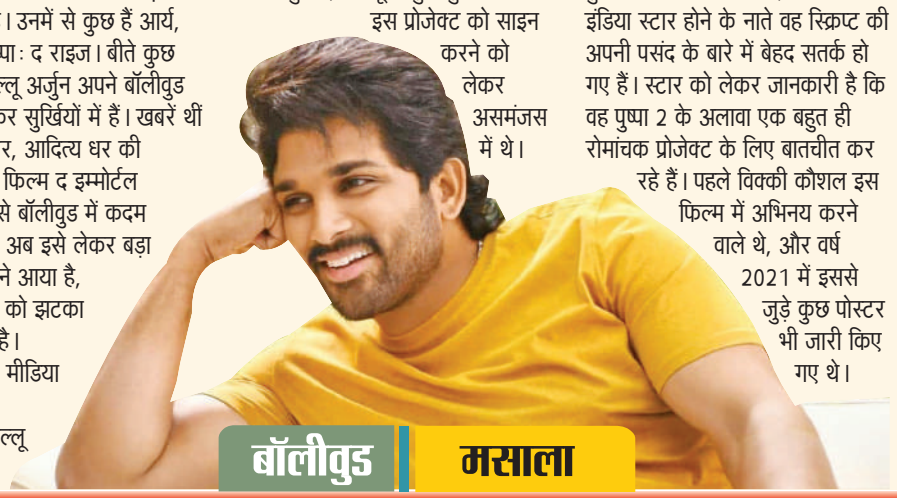

बॉलीवुड | मसाला

हालांकि, फिर भी उन्होंने सोचने और निर्णय लेने के लिए अपना समय लिया। पुष्पा की सफलता के बाद, एक पैन इंडिया स्टार होने के नाते वह स्क्रिप्ट की अपनी पसंद के बारे में बेहद सतर्क हो गए हैं। स्टार को लेकर जानकारी है कि वह पुष्पा 2 के अलावा एक बहुत ही रोमांचक प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रहे हैं। पहले विक्की कौशल इस फिल्म में अभिनय करने वाले थे, और वर्ष 2021 में इससे जुड़े कुछ पोस्टर भी जारी किए गए थे।

हालांकि, किसी कारणवश परियोजना को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। बाद में विक्की ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद निर्माताओं ने रणवीर सिंह से संपर्क किया, और उन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया।

ओम राउत की आदिपुरुष की भारी विफलता को देखने के बाद, अल्लू अर्जुन ने महसूस किया कि अश्वत्थामा एक जोखिम भरा प्रोजेक्ट था, और वह अनिश्चित थे कि क्या वह एक परियोजना में महत्वपूर्ण समय और प्रयास का निवेश करना चाहते हैं, जिसका परिणाम केवल दो वर्ष बाद ही पता चलेगा। इसलिए, उन्होंने अश्वत्थामा से अलग होने का फैसला किया। अल्लू अर्जुन अत्यधिक महत्वाकांक्षी फिल्मों से दूर रह सकते हैं, जो व्यावसायिक जोखिम बन सकती है।

अजब-गजब | आखिर कैसे बनती हैं चूड़ियां?

आसान नहीं है कांच की कारीगरी, जान जोखिम में डाल काम करते हैं लोग

चूड़ियों पर कितने ही शेर कहे गए, कितनी कविताएं लिखी गईं और कितने गीत बने पर चूड़ियां बनाने के पीछे की मेहनत के बारे में किसी ने नहीं बात की। चूड़ियों को हमेशा रोमैंटेसाइज किया गया है, उन्हें प्रेमिकाओं के हाथ से लेकर मांओं के हाथ तक की खूबसूरत बढ़ाने क लिए जाना गया, पर उन्हें बनाते-बनाते किसी मजदूर के हाथ कितनी बार जले, इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चूड़ी बनाने वाले कारीगरों की मेहनत का नमूना देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को देखकर आपको समझ आएगा कि उनका काम कितना मुश्किल है और वो जान जोखिम में डालकर काम करते हैं।

इंस्टाग्राम अकाउंट @ourcollecti®n पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में चूड़ी बनाने के पूरे प्रोसेस को दिखाया गया है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है जहां चूड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है और चूड़ी बनाने की बड़ी फैक्ट्रियां इस शहर में मौजूद हैं। वायरल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कारीगर कितनी मेहनत कर के चूड़ियों को बनाने का

काम करते हैं। वीडियो में सबसे पहले कांच को छोटे टुकड़ों में किया जा रहा है। उसके बाद उन टुकड़ों को छांटा जा रहा है। छांटे हुए टुकड़ों को खौलती भट्टी में झोंक दिया जाता है। इसके बाद कुछ लोग लोहे की सरिया में पिघले हुए कांच को फंसाकर उसे सीधा कर रहे हैं।

उसे पीट-पीटकर वो उसे आकार देते हैं और फिर जब वो पिघल हुआ रहता है तो उसे लोहे के रॉड में बांधकर चूड़ी का आकार देने लगते हैं। चूड़ी का शुरुआत शेप जब बन जाता है तो उसे आगे कई और प्रोसेस से गुजारा जाता है। तब जाकर चूड़ी आकार लेती है और बिकने के लिए तैयार होती है। इस वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने कहा कि ये बेहद खूबसूरत है, बस उन्हें मास्क पहनकर काम करना चाहिए। एक ने कहा कि इन लोगों की कड़ी मेहनत को सलाम। एक ने कहा कि फैक्ट्री का मालिक तो मोटी कमाई करता होगा, पर वो इन लोगों की आंखों की हिफाजत के लिए कुछ नहीं खरीद सकता।

इस एयरपोर्ट पर एक दशक से खड़ा हुआ है दूसरे देश का विमान, किराया पहुंचा सवा तीन करोड़

छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में आपातकाल के दौरान उतारे गए बांग्लादेशी विमान को यहां से सात अगस्त को आठ वर्ष पूरे हो गए हैं। इन आठ वर्षों में विमान का किराया लगभग सवा तीन करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। रायपुर विमानतल अथारिटी की ओर से इस विमान की नीलामी की तैयारी की जा रही है। विमानतल अथारिटी ने बांग्लादेशी कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। नीलामी के लिए कंपनी के जवाब का इंतजार है। वहीं विमानतल अथारिटी की ओर से अपने कानूनी सलाहकारों से इस संबंध में चर्चा की जा रही है। रायपुर विमानतल के निदेशक प्रवीण जैन ने बताया कि बांग्लादेशी कंपनी का जवाब आते ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सात अगस्त 2015 को बड़ी आपात स्थिति में ढाका से मस्कट जा रहे एमडी 83 विमान में खराबी की वजह से उसकी लैंडिंग रायपुर विमानतल में करवाई गई थी, जिसमें 173 यात्री शामिल थे। इसके बाद यात्रीगण को दूसरे विमान से भेज दिया गया था। इस घटना के बाद से वह बांग्लादेशी विमान रायपुर विमानतल में खड़ा है और उसकी नीलामी की तैयारी की जा रही है। 2019 में बांग्लादेशी विमानन कंपनी के विशेषज्ञों की ओर से रायपुर विमानतल पहुंचने के बाद उन्होंने इस विमान को 300 मीटर खिसकाया था। उन विशेषज्ञों ने यह भी बताया था कि विमान को जल्द से जल्द ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2015 से लेकर अब तक, रायपुर विमानतल अथारिटी ने बांग्लादेशी कंपनी को 70 से अधिक बार पत्र और ईमेल लिखे हैं। इस बार उन्होंने नीलामी के संदर्भ में बांग्लादेशी कंपनी को नोटिस जारी किया है और वर्तमान में कंपनी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं भाजपा-आरएसएस के लोग : राहुल

बोले- दादी ने बताया हिन्दुस्तान के पहले निवासी आदिवासी थे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासियों को संबोधित राहुल गांधी ने कहा कि भारत की जमीन आदिवासियों की जमीन है। देश की इस जमीन पर पहला हक आदिवासियों का है लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका हक देने के लिए कई कानून बनाए लेकिन बीजेपी ने उन्हें रद्द कर दिए। बुधवार 9 अगस्त को संसद में केन्द्र सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में भी बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया।

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें बताया कि हिन्दुस्तान के पहले निवासी आदिवासी थे। यह जो हमारी जमीन है जिसे हम भारत कहते हैं। यह जमीन आदिवासियों की जमीन थी। आज जो मॉर्डन समाज है उन्हें आदिवासियों से सीखना जिन्दगी जीना सीखना चाहिए। जल, जंगल और जमीन के साथ कैसा बर्ताव करना है। यह हमें आदिवासियों से सीखना चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। यानी जंगल में रहने वाले लोग। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ तो आदिवासियों को जंगल की ओर धकेला जा रहा है और दूसरी तरफ जंगलों को काट काट कर खत्म किया जा रहा है। आने वाले दिनों में पूरे जंगल खत्म कर दिए जाएंगे और आदिवासियों की पूरी जमीनें छीन ली जाएगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीनें छीन कर अडाणी को दी जा रही है।

पूरे देश का अपमान करती है बीजेपी

आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि आदिवासियों को उनका हक मिले। आदिवासियों के बच्चे भी कॉलेज और युनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करें। कम्प्युटर चलाएं, बिजनैस करें और तेजी से आगे बढ़ें। आप जो सपना अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, वे सपने पूरे होने चाहिए लेकिन बीजेपी को लोग चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहो। वनवासी बताकर जंगल में धकेला जा रहा है। वे चाहते हैं कि आप वहीं रहो। यह केवल आपका अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है।

आदिवासी को विदेशी बताना अपमान : कमलनाथ

मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर सियासत तेज है। विश्व आदिवसी दिवस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि आदिवासी समाज हमारे प्रदेश के मूल निवासी है, जल, जंगल, जमीन का असली हकदार यही समाज है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को विदेशी बताना आदिवासियों को अपमान है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग पर अत्याचार में नंबर वन पर है। उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासी समाज सबसे सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का चित्र हमारे सामने है। भाजपा क्या कहेगी आज, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पूरा भारत मना रहा है, पर भाजपा छोड़ो दिवस भी मना रहा है। प्रदेश को कहां घसीटा जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इससे पहले आदिवासियों के नाम एक संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को हक दिलाने का काम किया। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में हर काम किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पेसा कानून कांग्रेस ने बनाया, वन अधिकारों का कानून भी कांग्रेस की देन है। आदिवासी समाज और कांग्रेस पार्टी एक परिवार है।

राहुल गांधी ने आदिवासियों को बचपन की कहानी सुनाई और रवाना हो गए : सीपी जोशी

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चंद महीनों का समय बचा है। जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से तैयारियां करने में जुटी है। इस बीच राहुल गांधी के मानगढ़ धाम दौरे को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक कटाक्ष किया है। भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने आदिवासियों को अपने बचपन की कहानी सुनाई और चले गए। राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान में भीलवाड़ा दुष्कर्म हत्याकांड की बात क्यों नहीं की। उन्होंने वागड़ और मेवाड़ की जनता का अपमान किया है, उस क्षेत्र में विकास कार्य का लेखा जोखा भी राहुल गांधी को बताना चाहिए था। जिसको लेकर वह चुप रहें, इसके लिए कांग्रेस को मांफी मांगनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यमुना नदी की स्टेटस रिपोर्ट

दिल्ली-हरियाणा सरकार को आदेश, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह बताया गया है कि यह उचित होगा कि इन मुद्दों को विभाजित करके सुना जाए ताकि उपचारात्मक उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उस दृष्टि से, हम पहले यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित मुद्दे को सुनना उचित समझते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली से यमुना नदी के प्रदूषण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि वह 3 अक्टूबर को इस मुद्दे पर विचार करेगा। मंगलवार को शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके ध्यान में लाया गया है कि यमुना और तटीय क्षेत्रों के प्रदूषण और उपचारात्मक उपायों से संबंधित मामले उसके समक्ष हैं। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह बताया गया है कि यह उचित होगा कि इन मुद्दों को विभाजित करके सुना जाए ताकि पचारात्मक उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उस दृष्टि से, हम पहले यमुना नदी के प्रदूषण से संबंधित मुद्दे को सुनना उचित समझते हैं। उस संबंध में, स्थिति रिपोर्ट हरियाणा राज्य और दिल्ली राज्य द्वारा अलग से दायर की जाएगी।

महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में हुई सुनवाई

बृजभूषण ने अदालत से कहा- गले लगाना अपराध नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि यौन इरादे के बिना किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष आरोपी ने बुधवार को अपने खिलाफ आरोप तय करने का विरोध करते हुए अपने वकील के माध्यम से दलीलें दीं।

अदालत ने बुधवार को सिंह और सह-आरोपी और निलंबित डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के बिंदु पर बहस शुरू की। सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने अदालत को आगे बताया कि आरोप कालातीत हैं। ये दिखावटी आधार यह नहीं मानेंगे कि शिकायतकर्ता खतरे में थे। यदि शिकायतकर्ता स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और पांच साल तक आप आगे नहीं आए और फिर यह कहना कि आप खतरे में थे, यह वैध स्पष्टीकरण नहीं है। वकील ने कहा कि अदालत के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि अपराध कथित तौर पर भारत के बाहर किए गए हैं।अगर हम इन आरोपों को लें, तो भारतीय क्षेत्राधिकार इनमें से केवल तीन आरोपों में निहित है। भारत के बाहर किए गए अपराधों पर मंजूरी की कमी के कारण अदालत द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दो अपराध अशोक रोड और सिरी फोर्ट से संबंधित हैं। सिरी फोर्ट में अपराध सिर्फ गले लगाने का है। किसी महिला को बिना किसी आपराधिक बल या यौन इरादे के छूना अपराध नहीं है।

मोहन ने कहा कि कुश्ती एक ऐसी प्रतियोगिता है, जिसके ज्यादातर कोच पुरुष ही होते हैं। महिला कोच दुर्लभ हैं। अगर कोई कोच किसी उपलब्धि के बाद खुशी के मारे किसी खिलाड़ी को गले लगा रहा है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। घटना ऐसी है और अगर कोई पुरुष कोच किसी खिलाड़ी को चिंता के कारण गले लगाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत इस मामले पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।

शुभमन गिल और कुलदीप ने लगाई छलांग

वनडे रैंकिंग : बल्लेबाजी में टॉप-5 में गिल, गेंदबाजी में यादव शीर्ष 10 में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

दुबई। आईसीसी वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल ने 2 नंबर की छलांग लगाई है। जिसके बाद वो टॉप 5 में काबिज हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी।

वहीं गिल और ईशान किशन दोनों ही तीन मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद काफी फायदा हुआ है। जबकि कुलदीप यादव को भी आईसीसी गेंदबाजी रैंकिंग में अच्छी गेंदबाजी का लाभ मिला है। दरअसल, आईसीसी वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल ने 2 नंबर की छलांग लगाई है। जिसके बाद वो टॉप 5 में काबिज हो गए हैं। वहीं ईशान किशन को भी वनडे रैंकिंग में काफी बड़ा फायदा हुआ है।

बता दें कि, पाकिस्तान के बाबर आजम वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। जबकि साउथ अफ्रीका के रासी वैन डेर डुसेन 777 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे पर 755 अंकों के साथ फखर जमान और इमाम उल हक 746 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो,भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर 7 विकेट झटके थे। जिसकी बदौलत वो 10वें स्थान पर हैं।

अब 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा भारत-पाक मुकाबला

विश्व कप का बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला अपनी मूल तारीख 15 अक्टूबर से बदलकर 14 अक्टूबर कर दिया गया है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस मैच की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने बुधवार को विश्व कप 2023 के लिए संशोधित कार्यक्र म की घोषणा की। आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला गुरुवार, 12 अक्टूबर से अब मंगलवार, 10 अक्टूबर को खेला जाएगा और लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मैच 24 घंटे पीछे चला गया है और अब शुक्रवार 13 अक्टूबर के बजाय गुरुवार, 12 अक्टूबर को खेला जाएगा।

सदन की झलकियां सदन के चौथे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव व शिवपाल यादव समेत सत्ता व विपक्ष के माननीयों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। इस दौरान महिला सदस्यों की भी पर्याप्त उपस्थिति रही।

सदन में विपक्ष के निशाने पर सरकार

यूपी विधानसभा के मानसूत्र सत्र का चौथा दिन, हंगामा जारी, शिवपाल ने कहा- मंत्री सुन लेते हैं अफसर नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आज यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। सदन 11 अगस्त तक चलेगा। सदन की कार्यवाही में सीएम योगी मौजूद रहेंगे । विभिन्न मुद्दों को लेकर आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। इससे पहले बुधवार को सदन में सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे उनका फोन नहीं उठाते जबकि मंत्री जी फोन उठा लेते हैं।

उन्होंने सिंचाई और खाद मिलने में किसानों को आ रही समस्याओं का जिक्र किया और सरकार से इसका समाधान करने की अपील की। सदन में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार और प्रदेश के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नहरों में पानी न होने का जिक्र करते हुए प्रदेश के धान किसानों की समस्याएं गिनाईं। साथ ही उन्होंने अपनी एक व्यथा का भी जिक्र सदन में किया और कहा कि कोऑपरेटिव के प्रमुख सचिव उनका फोन भी नहीं उठाते। उनकी शिकायत पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में हस्तक्षेप किया है। आप जैसे वरिष्ठ का फोन अगर वह नहीं उठाते तो गलत बात है। शिवपाल सदन में सिंचाई विभाग में अव्यवस्था को लेकर सदन में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि किसानों को इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि उन्हें अब कोई परेशानी ही नहीं है जबकि किसानों को खाद कहीं पर भी नहीं मिली। सरकार किसानों को बिजली भी नहीं दे पा रही है।

नहरों में पानी नहीं है, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी हो रही है। बिजली न होने से वो ट्यूब्ल इत्यादि का प्रयोग भी सिंचाई के लिए नहीं कर पा रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि हमारी तरह अगर सरकार साल में दो बार नहरों की सफाई कराती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। शिकायती लहजे में शिवपाल ने कहा कि आपके अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो किसी का फोन ही नहीं उठाते। सिंचाई विभाग का पता नहीं क्या होगा जब सचिव फोन ही नहीं उठा रहे जबकि मंत्री जी तो उठा लेते हैं। इस पर स्पीकर सतीश महाने ने उन्हें आश्वासन दिया कि अधिकारी फोन उठाएंगे। महाना ने कहा कि सीएम योगी ने कह दिया है। अगर वह आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का फोन नहीं उठाते तो यह गलत है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा।

भाजपा सरकार में लगातार गिर रहा है शिक्षा का स्तर : आशुतोष

लखनऊ। विधान परिषद में सपा सदस्यों ने शिक्षा और शिक्षामित्रों के मुद्दे पर वॉकआउट किया। मुख्य विपक्षी दल का कहना था कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सपा के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि आरएमएसए के तहत खोले जा रहे स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का वेतन रुका है। मान सिंह यादव ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के लिए अभी तक नियमावली नहीं बनी है। लाल बिहारी यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ न्याय नहीं कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने आरोपों को नकारते हुए अपने विभाग की उपलब्धियों को रखा। इससे असंतुष्ट सपा सदस्यों ने वॉकआउट किया। बसपा के भीमराव अंबेडकर ने विनहट में किसानों की अधिग्रहीत भूमि वापस करने की मांग की। सरकार की ओर से जवाब देते हुए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि इस बारे में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है।

चुनाव अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पर आएगा नया बिल

» सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले पर पड़ेगा असर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्र एक ऐसे कानून को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने की संभावना है। मोदी सरकार के इस बिल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर देगा।

इसी सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) बिल, 2023 आज राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। इसमें प्रस्ताव है कि मतदान अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पैनल की अध्यक्षता करेंगे, वास्तव में, बिल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को कमजोर करना है जिसमें एक संविधान पीठ ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति , चुनाव आयुक्तों का चयन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पैनल की सलाह पर किया जाएगा।

नूंह हिंसा के दो आरोपियों से मुठभेड़, एक घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नूंह। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल धाम जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन लगातार उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामले में पुलिस ने नूंह हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर किया है। बताया जा रहा है कि उपद्रवी सिलखो गांव की पहाड़ी में छिपे थे।

एनकाउंटर के दौरान एक उपद्रवी को पैर में गोली लगी है, दूसरे को गोली नहीं लगी उसे पकड़ लिया गया है। उसे घायल हालत में इलाज के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में आरोपित ने पहले क्राइम ब्रांच तावडू के प्रभारी संदीप मोर की टीम पर फायरिंग की थी। अपने बचाव में जब इंस्पेक्टर संदीप मोर ने गोली चलाई तो वह एक आरोपित के पैर में जा लगी। बता दें कि इससे पहले आरोपितों की खोज में लगी एसटीएफ ने बुधवार सुबह ड्रोन की मदद से पहाड़ी पर ठिकाना तलाश कर नौ लोगों को हिरासत में ले लिया था। सभी नल्हड़ और मेवली गांव के रहने वाले हैं।

रेपो रेट नहीं बढ़ेंगे : गवर्नर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों को सुनाते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज नई मौद्रिक नीति का एलान किया। 8 से 10 अगस्त तक चले एमपीसी की बैठक में एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया। यह लगातार तीसरी बार है जब एमपीसी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अप्रैल और जून में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा गया था।

आज एक बार फिर से गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा कि फिलहाल रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर ही स्थिर रहेगा। आपको बता दें कि 6 सदस्य वाली एमपीसी के सामने रेपो रेट के अलावा देश में बढ़ रही महंगाई, अर्थव्यवस्था इत्यादि जैसे तमाम मुद्दे थे जिसके मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था।

फरवरी में एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया था। फरवरी में रेपो रेट में हुए इस बदलाव को मिलाकर मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो रेट में 250 आधार अंकों यानी 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।